out in the newspapers but it has not been denied. That is the point I would like to know.

MR. CHAIRMAN: He categorically said, no such instructions have been issued.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Then why not deny the newspaper report?

MR. CHAIRMAN: They are denying it.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: They cannot give instructions to the foreign Embassies. Is there a letter just written to the Ministry? (*Interruptions*). Is there any letter just received by the Ministry? ....(*Interruption*)...

SHRI A. G. KULKARNI: How is it possible? It is on fake passport they are talking...

MR. CHAIRMAN: Dr. Sivaji .... (*Interruptions*)....

महाजन साहब, जरा बैठिए । आप तो पुराने आदमी हैं ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, I will give them a specific instance...

श्री सभापति : जनरल साहब, आप भी बैठिए । कुछ तो डिसिप्लिन होता है आप तो जनरल हैं ।....(व्यवधान)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: While applying for a passport it is to be certified by an official of the rank of Deputy Secretary. Are there any instances in the knowledge of the Government where the authorities have certified untruths and half-truths while certifying the passport applications?

SHRI M. M. JACOB: Sir, the question is not clear.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: While applying for a passport it is warranted that it is to be certified...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, he should ask the External Affairs Minister, not the Home Minister. ... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The question is of fake passports.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, you don't allow such questions.....

MR. CHAIRMAN: Nobody applies for a fake passport. .... (*Interruptions*)...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: While applying for a passport it is to be certified by an official not below the rank of District Magistrate. Are there any instances in the knowledge of the Government....

MR. CHAIRMAN: Dr. Sivaji, the question is restricted to fake passports.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, it is in regard to only fake passports.

MR. CHAIRMAN: Do you get a recommendation from your District Magistrate for a fake passport?

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Are there any instances in the Ministry of Home Affairs in regard to these certificates for fake passports?

SHRI M. M. JACOB: It is not in my knowledge. Sir, fake passports are not issued by the Ministry.

MR. CHAIRMAN: He wants you to find out from the State Government or the District authorities as to who recommends for fake passports.

SHRI M. M. JACOB: We have written to the Andhra Pradesh Government for furnishing information about fake passports.

MR. CHAIRMAN: Now let us proceed from fake passports to Question No. 44.

Decentralisation of DTC Routes

*44. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the short distance routes of D.T.C. are uneconomical;

(b) whether it is also a fact that there is greater need for decentralisation of DTC routes;

(c) if so, what steps Government propose to take in the matter; and

(d) what are the routes on which private buses under DTC operation are operating and the same have been rationalised during the last twenty months?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is need to rationalise DTC routes. This is a countinuing process which DTC have been carrying out on a regular basis.

(d) During the last 20 months, rationalisation of two routes, namely, Nos. 407 and 10-Spl. have been made. Details of the changes made in these routes are as under:—

Route No.	Old Route	Modified Route	Date w.e.f.
407	Lajpat Nagar to Dhaula Kuan	Lajpat Nagar to R.K. Puran	6.6.1991
10-Spl.	Kalyan Vihar to Kendriya Terminal via panwadi Road.	Kalyan Vihar to Kendriya Terminal via G.T.Road R/T Road, Gujaran Wala.	19.3.91

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : सर, मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि डी०टी०सी० की बसों में वाकया होती हुई मुसलसल कमी, सफर करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा, दर्ज फेहरिस्त ट्रिपों की तादाद में रोज-ब-रोज होती हुई कमी, बड़ी तदाद में दर्ज फेहरिस्त ट्रिपों का न चलना, वक्त की पाबंदी का न होना, लापरवाह नाएहल और गैर-डिसिपिलिन स्टाफ का होना, स्टाफ की सवारियों के साथ बदतमीजी, टाईम-कीपरों का स्टाफ के साथ मिलीभगत, बसों का डिपो से देर से निकाला जाना, बसों की खराब हालत, बहुत पुरानी बसें और उनका खराब रख-रखाव, सामान की बड़े पमाने पर चोरी और हेराफेरी, जैसे मसायल से निपटने के लिए सरकार के पास क्या स्कीमें हैं ?

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی : سر میں منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈی ٹی سی کی بسوں میں واقع ہوتی ہوئی مسلسل کمی - سفر کرنے والوں کی تعداد میں مستقل اضافہ - درج فہرست ٹرپوں کی تعداد میں روز بروز ہوتی ہوئی کمی - بڑی تعداد میں درج فہرست ٹرپوں کا نہ چلنا- وقت کی پابندی نہ ہونا - لاپرواہ نااہل اور غیر ذمہ اسٹاف کا ہونا- اسٹاف کا سواریوں کے ساتھ بدتمیزی- ٹائم کیپروں کی اسٹاف کے ساتھ ملی بھگت - بسوں کا ڈپو سے دیر سے نکالا جانا - بسوں کی خراب حالت - بہت پرانی بسیں اور انکا خراب رکھ رکھاؤ - سامان کی بڑے پیمانے پر چوری اور ہیرا پھیری جیسے مسائل سے نپٹنے کیلئے سرکار کے پاس کیا اسکیمیں ہیں -]

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री जगदीश टाइटलर : यह सच है कि डी०टी०सी० के दिल्ली में 739 रूट्स हैं और 40 लाख लोग दिल्ली के रोज इसमें सफर करते हैं । हमारे पास सातवीं योजना के आखिर में जो बसों की जरूरत थी, वह 7,500 बसों की थी मगर आज हमारे पास सिर्फ 4,387 बसें हैं । इसके अलावा कुछ प्राइवेट बसें भी चलती हैं । इसी कारण, क्योंकि सवाल का पहला पार्ट है कि दिल्ली के लोगों को काफी तकलीफ है, उसके कारण हम एक नई स्कीम ले रहे हैं जो अगले एक-दो महीने में आ जाएगी और जिसको इम्प्लीमेंट करने में चार-पांच महीने जरूर लगेंगे जिसमें मेरा विचार है कि हम दिल्ली में 3000 बसों को नए परमिट देकर, प्राइवेट लोगों को, हम दिल्ली के लोगों को और सुविधा दे सकेंगे ।

प्रश्न का दूसरा जो हिस्सा है कि जो बेइमानी होती है बसों के अंदर, बसों के डिपार्टमेंट के अंदर, जो लोगों के साथ बदतमीजी होती है, उसके लिए हमने वहां के चेयरमन को पहले ही कह रखा है कि जो डी०टी०सी० का एम्प्लाई पब्लिक के साथ बदतमीजी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए । हम पूरी कोशिश कर रहे है कि जो भी चोरी या हेराफेरी डी०टी०सी० में होती है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए ।

मोलाना अब्दुल्ला खान आजमी : मेरा दूसरा सवाल यह है कि डी०टी०सी० का खुला दरबार महज दिखावा है और लोगों की दरख्वास्तों एवं मश्विरों का मुस्तरद किया जाना, रूटों की लंबाई का न बढ़ाया जाना, जिन रूटों पर प्राइवेट बसें लगा रखी हैं उनको रेशनलाइजेशन न किया जाना, बस-स्टापों पर शेड्स की कमी, बस टर्मिनल की कमी, मनेजरों की एहलियत व काबलियत में गिरावट और उनके लंबे अरसे तक तबादले न होना जैसे मसायल से निबटने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है ?

†مولانا عبیداللہ خان اعظمی : میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دربار محض ایک دکھاوا ہے اور لوگوں کی درخواستوں اور مشوروں کا مسترد کیا جانا - روٹوں کی لمبائی کا نہ بڑھایا جانا ! جن روٹوں پر پرائیویٹ بسیں لگا رکھی ہیں انکا ریشنالائزیشن نہ کیا جانا - بس اسٹاپوں پر شیڈس کی کمی - بس ٹرمینلس کی کمی - منیجروں کی اہلیت اور قابلیت میں گراوٹ اور انکے لمبے عرصے تک تبادلے نہ ہونا - جیسے مسائل سے نپٹنے کیلئے سرکار کے پاس کیا اسکیم ہے -]

श्री जगदीश टाइटलर : ऐसा है कि तकरीबन सारे के सारे रूट्स जो दिल्ली से चलाए जाते हैं, उनमें हमें नुकसान हो रहा है । जैसा मैंने बताया कि 739 रूट्स में से केवल एक रूट है जिसमें हम नुकसान नहीं उठा रहे हैं..... (व्यवधान)...

SHRI A. G. KULKARNI: Are you issuing permits to private operators?

श्री जगदीश टाइटलर : वह तो हमने कह दिया कि अगले तीन महीने में हम तीन हजार परमिट, जो दिल्ली में बसों की कमी हैं, उसे देखते हुए दे रहे है और यह कमी दूर हो जाएगी ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूं कि दिल्ली में महिलाएं भी बसों में सफर करती हैं खासकर के यूनिवर्सिटी एरिया में विद्यार्थी, लड़कियां भी बस में चढ़कर जाती हैं और उनके साथ अक्सर जाते समय भी और वापिस आते समय भी, बस के कंडक्टर, बस के एम्प्लाइज के द्वारा दुर्व्यवहार होता है । यह बार-बार समाचार-पत्रों में भी आया है । तो इस तरह के केस में सरकार क्या करना चाहती है ? क्या कोई विशेष सुविधा यूनिवर्सिटीज के लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी या नहीं ?

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

और दूसरा मेरा सवाल है कि जो कामगार औरतें बसों से शहर के अन्य इलाकों में जाती हैं क्या उनके लिए आप कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ? अभी आपने कहा कि निजी बस मालिकों को हम परमिट देंगे, तो क्या इस मामले में कोई निजी महिला अगर बस चलाना चाहे तो उसको परमिट देकर बस देंगे और कोई विशेष सुविधा देंगे या नहीं ?

श्री जगदीश टाइटलर : सुविधा तो जो सबको मिलेगी, वह महिलाओं को भी मिलेगी, मगर यह बात जरूर है कि अगर महिलाएं बस चलाना चाहती हैं तो हम जो तीन हजार परमिट दे रहे हैं उसमें कुछ कोटा लेडीज के लिए भी रख देंगे ।

श्री सभापति : वह छेड़-छाड़ की बात कर रही थी । उनके साथ व्यवहार ठीक हो—कामगार महिलाओं के साथ भी और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ।

श्री जगदीश टाइटलर : दिल्ली में आजकल डी०टी०सी० स्टूडेंट्स स्पेशल और लेडीज स्पेशल तो चलाती है और जहां-जहां भी हमें खबर मिलती है छेड़-छाड़ की, तो डी०टी०सी० की मेनेजमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करती है ।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, why can't they have 'Ladies Special' buses where only ladies are permitted?

SHRI YASHWANT SINHA: Arising out of the reply which the Minister has just now given about the induction of 3000 private buses, I would like to ask him a question. There are already private buses in operation under the DTC. Now, under this new scheme, will these route permits be issued by the Director of Transport, Delhi Administration, or will they be under the same arrangement which exists in the DTC that buses are taken on certain payment? Now, there was something in the past like the AOCC scheme which was changed by Mr. Rajesh Pilot when he was the Minister for Surface Transport. And subsequently the conductors in these private buses were allowed to collect the fares and keep them, like the other arrangement which had existed in DTC for many years. Therefore, the first part of the question is whether the new arrangement will be an arrangement under the Motor Vehicles Act made by the Director of Transport or whether they will be under the DTC. Secondly, of late there have been studies in Delhi about the designed capacity of Delhi roads to take a certain number of buses and Delhi cannot take any more buses than the buses which the DTC plies both of its own fleet and of the private operators. And there are a large number of private buses which are plying on contract. What I would like, therefore, to ask the honourable Minister is whether any fresh study has been made of the designed capacity of Delhi roads and how many buses Delhi roads can take. Or, are you going to choke this city to death, because you are going on indiscriminately increasing the number of buses under the DTC or under the Transport Department without thinking of a mass rapid transit system?

SHRI JAGDISH TYTLER: First of all, I would like to inform the honourable Member that permits are going to be given by the Director of Transport who comes under the Delhi Administration. Private buses which are run under the DTC today are 630 and there are about 427 permits which have been given for stage carriages by the State Transport Authority. There are over 2,000 contract carriage buses which are also running. There has been a survey which was done—I do not exactly know in which year it was done. But this addition of 3,000 buses which I had planned, my department had planned, is not going to be done in a way that would completely choke Delhi. Routes are going to be identified and these permits are going to be given on particular routes and these routes will be spread all over Delhi so that choking does not take place. Apart from that you see the kind of transport with which the city is getting congested everyday, the bottlenecks that are there otherwise. I will see to it that we don't add more to it.

We shall see that it is done in such a way that the whole of Delhi is covered. Permits are going to be given on particular routes. The number of permits and the routes are going to be identified. The kind of people and the number of people travelling, all these things are going to be identified.

Facility of Car Telephone in the Country

*45. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the facility of car telephone is available in the country;

(b) if so, what are the details in this regard including the number of car telephones and expenditure incurred;

(c) whether the MTNL, Bombay proposes to provide the facility in the city of Bombay; and

(d) if so, what are the details in this regard including import of machinery, if any?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes Sir, the facility of car telephone is presently available only at Delhi.

(b) Sir, there are at present 177 subscribers connected to the mobile system at Delhi. Initial investment for this system was Rs. 2.18 crores. An additional investment of Rs. 2.41 crores has been made to augment the capacity to give connections to more subscribers.

(c) and (d) This proposal is at a preliminary stage of technoeconomic examination.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, श्रीमंतों से, कुछ सुविधायें देने के लिये पर्याप्त धन वसूल कर गरीबों के लिये खर्च करने की किसी भी योजना का मैं समर्थन करता हूं । मंत्री जी की नीयत भले कितनी भी ठीक हो, इसकी नीति में हमेशा गड़बड़ होती है ।

श्री एन०के०पी० साल्वे : नजर में फर्क है ।

श्री प्रमोद महाजन : जैसे हमने साधारण और दूर-ध्वनि का मालिक, इसकी चर्चा की । साधारण टेलीफोन वाला एक हजार रुपया देता है .... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : अभी कार पर आ जाओ, कार वाले की बात करो ।

श्री प्रमोद महाजन : उसी में कार आती है .... (**व्यवधान**) उस क्वेश्चन में आपने कार का एलाउ किया । नहीं, मैं केवल उसका उदाहरण दे रहा हूं । दूर-ध्वनि का मालिक आठ हजार रुपया लेता है, एक तो बीस वर्ष लगते हैं और एक को पांच वर्ष लगते हैं । तो अब एक हजार रुपया आपके पास 20 साल रहे और आठ हजार रुपया चार साल रहे तो मतलब एक ही निकलता है ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये । आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद महाजन: उसी प्रकार मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो दिल्ली में टेलीफोन कार उपयोग करने वाले 177 उपभोक्ता हैं उसके लिये आपने आरम्भिक निवेश दो करोड़ अठारह लाख रुपया किया है । एक लाख रुपया आप हर एक से लेते है । इसका मतलब आपने अभी तक इनसे दो करोड़ रुपया भी वसूल नहीं किया है । एक लाख आप हरेक से लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक दो करोड़ रुपया भी वसूल नहीं किया है । अगर श्रीमन्तों से पैसा लेना है तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या कार टेलीफोन का पैसा बढ़ाकर जितनी कीमत इसकी है, उससे 10 प्रतिशत ज्यादा लिया जाएगा ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इसमें सरकारी टेलीफोन कितने हैं और निजी टेलीफोन कितने हैं? मैं यह भी जानना चाहता